NEXT IAS

दैनिक समसामयिकी विश्लेषण

समय: 45 मिनट

दिनाँक: 08-02-2025

विषय सूची

दुर्लभ बीमारी के लिए वित्तीय सहायता

लॉजिस्टिक चुनौतियों से निपटने के लिए e-NAM को उन्नत किया जाएगा

भारत का सोने में निवेश 2024 में 60% बढ़कर 1.5 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा

फेसियल रिकॉग्निशन सिस्टम (FRS)

भारत ने 100 GW सौर ऊर्जा क्षमता का ऐतिहासिक माइलस्टोन प्राप्त किया

संक्षिप्त समाचार

अभियुक्त को गिरफ़्तारी के आधार की जानकारी देना संवैधानिक आवश्यकता

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग

शतावरी (एस्पेरेगस रेसमोसस)

संयुक्त राज्य अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (USAID)

एल्गो ट्रेडिंग फ्रेमवर्क

पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन(NBM)

भारत की सबसे बड़ी सौर सेल बनाने वाली इकाई

ट्रोपेक्स (TROPEX) अभ्यास

दुर्लभ बीमारी के लिए वित्तीय सहायता

समाचार में

- सरकार ने दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति के अंतर्गत पहचान की गई दुर्लभ बीमारियों से पीड़ित रोगियों के उपचार के लिए 50 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता की घोषणा की है, जिसमें दुर्लभ बीमारियों की 63 श्रेणियाँ सम्मिलित हैं।

दुर्लभ बीमारी के बारे में

- दुर्लभ रोग एक ऐसी स्वास्थ्य स्थिति है जिसका प्रसार कम होता है, तथा जो सामान्य जनसंख्या में होने वाली अधिक सामान्य बीमारियों की तुलना में कम संख्या में लोगों को प्रभावित करती है।
- दुर्लभ रोगों की कोई सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत परिभाषा नहीं है, तथापि, वे सामान्यतः अपनी कम व्यापकता, गंभीरता और प्रायः वैकल्पिक उपचारों की कमी के कारण पहचाने जाते हैं।
  - इनमें आनुवंशिक रोग, दुर्लभ कैंसर, संक्रामक उष्णकटिबंधीय रोग और अपक्षयी रोग सम्मिलित हैं।
- विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के अनुसार दुर्लभ रोग, प्रायः आजीवन दुर्बल करने वाला रोग या विकार की स्थिति है, जिसकी व्यापकता प्रति 1000 जनसंख्या पर 1 या उससे कम होती है।

मुद्दे और चिंताएँ

- **व्यापकता:** भारत में वैश्विक दुर्लभ बीमारियों के एक तिहाई मामले सामने आते हैं, जहाँ 450 से अधिक पहचाने गए रोग हैं, जिनसे 8-10 करोड़ लोग प्रभावित हैं, जिनमें मुख्य रूप से बच्चे हैं।
  - हालाँकि, भारत में दुर्लभ बीमारियों की व्यापक स्तर पर उपेक्षा की जाती है।
- **मानक परिभाषा का अभाव:** भारत में दुर्लभ बीमारियों के लिए मानक परिभाषा का अभाव है। इस समस्या के समाधान के प्रयासों के बावजूद यह अंतर कायम है।
- **निदान संबंधी चुनौतियाँ:** औसतन, दुर्लभ रोगों के निदान में सात वर्ष लग जाते हैं, तथा स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर प्रायः लक्षणों की सही व्याख्या करने में असमर्थ होते हैं।
- **वित्तपोषण संबंधी मुद्दे:** दुर्लभ बीमारियों के लिए बजट कम बना हुआ है।

पहल

- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा मार्च 2021 में दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति (NPRD) प्रारंभ की गई थी।
  - दुर्लभ रोगों पर केन्द्रीय तकनीकी समिति (CTCRD) की सिफारिशों के आधार पर, वर्तमान में 63 दुर्लभ बीमारियों को नीति के अंतर्गत शामिल किया गया है।
  - दुर्लभ रोगों के निदान, रोकथाम और उपचार में विशेषज्ञता रखने वाले प्रमुख सरकारी अस्पतालों के रूप में 12 उत्कृष्टता केंद्रों (CoEs) की पहचान की गई।
- दुर्लभ बीमारियों के लिए आयातित दवाओं पर GST और सीमा शुल्क से छूट।
- अनुसंधान गतिविधियों को सुव्यवस्थित करने के लिए दुर्लभ रोगों के लिए चिकित्सा पर अनुसंधान एवं विकास हेतु राष्ट्रीय कंसोर्टियम (NCRDTRD) की स्थापना की गई थी।
- ICMR ने दुर्लभ रोगों पर एक बाह्य कार्यक्रम टास्क फोर्स का गठन किया है तथा दुर्लभ रोगों के लिए स्वदेशी उपचार विकसित करने पर केन्द्रित 19 परियोजनाएँ प्रारंभ की हैं।

सुझाव और आगे की राह

- दुर्लभ रोग के रोगियों के लिए समय बहुत महत्त्वपूर्ण है, और सरकार को प्रभावित व्यक्तियों के जीवन में सुधार लाने के लिए इन मुद्दों का तत्काल समाधान करना चाहिए।
- सरकार को दुर्लभ बीमारियों को परिभाषित करने, औषधि विकास को बढ़ाने, उत्कृष्टता केंद्रों (CoEs) के समन्वय में सुधार करने तथा समर्पित वित्त पोषण उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।
- राज्य सरकारों को सामाजिक सहायता कार्यक्रम और उपग्रह केंद्र प्रारंभ करने चाहिए, जबकि निजी कंपनियाँ CSR पहल के माध्यम से सहायता कर सकती हैं।

- सरकार को घरेलू निर्माताओं को प्रोत्साहित करना चाहिए तथा दवाओं के पुनः उपयोग पर विचार करना चाहिए, जिससे नैदानिक परीक्षण की आवश्यकताएँ कम हो जाएँ।

Source :TH

लॉजिस्टिक चुनौतियों से निपटने के लिए e-NAM को उन्नत किया जाएगा

संदर्भ

- केंद्रीय कृषि मंत्री ने अंतर-राज्यीय और अंतर-मंडी व्यापार में रसद संबंधी बाधाओं को हल करने के लिए राष्ट्रीय कृषि बाजार (e-NAM) को e-NAM 2.0 में अपग्रेड करने की योजना की घोषणा की है।

e-NAM के बारे में (2016)

- e-NAM एक अखिल भारतीय इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो कृषि उपज बाजार समिति (APMC) मंडियों को जोड़ता है ताकि कृषि वस्तुओं के लिए एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाया जा सके।
  - कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत लघु कृषक कृषि व्यवसाय कंसोर्टियम (SFAC) द्वारा कार्यान्वित।
  - व्यापारियों, किसानों, किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) और मंडियों को डिजिटल सेवाएँ प्रदान करता है।
  - 31 दिसंबर 2024 तक 1.79 करोड़ किसान और 2.63 लाख व्यापारी इस प्लेटफॉर्म पर पंजीकृत हो चुके हैं।

e-NAM में प्रमुख चुनौतियाँ

- 23 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों की 1,361 मंडियों को एकीकृत करने और 2.79 लाख करोड़ रुपये के व्यापार की सुविधा प्रदान करने के बावजूद, कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं:
  - **संभार-तंत्र संबंधी मुद्दे:** अकुशल परिवहन के कारण पारगमन समय अधिक लगता है तथा वितरण दक्षता सीमित हो जाती है।
  - **अपर्याप्त भंडारण एवं भण्डारण:** उचित भंडारण सुविधाओं के अभाव से फसल-उपरान्त हानि होती है।
  - **सीमित डिजिटल साक्षरता और इंटरनेट पहुँच:** कई किसान ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सामना करते हैं।
  - **अंतरराज्यीय व्यापार बाधाएँ:** राज्य APMC कानूनों में भिन्नताएँ सुचारू व्यापार में बाधा डालती हैं।
    - विभिन्न राज्य कर और अनुपालन मानक जटिलता उत्पन्न करते हैं।

e-NAM 2.0 की मुख्य विशेषताएँ

- **एकीकृत लॉजिस्टिक्स और परिवहन सहायता:** उपज की वास्तविक समय ट्रैकिंग के लिए एकीकृत लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (ULIP) एकीकरण।
  - पारगमन समय को कम करने और वितरण दक्षता में सुधार करने के लिए अनुकूलित माल ढुलाई विकल्प।
- **विस्तारित भंडारण और शीत भंडारण अवसंरचना:** कृषि अवसंरचना कोष (AIF) भंडारण सुविधाओं में निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी वाले ऋण की पेशकश करेगा।
- **AI-संचालित मूल्य खोज और गुणवत्ता मूल्यांकन:** AI और मशीन लर्निंग (ML) उचित बाजार मूल्यों का सुझाव देंगे।
  - उत्पाद ग्रेडिंग पर विवादों को कम करने के लिए स्वचालित गुणवत्ता परीक्षण।
- **तीव्र डिजिटल भुगतान और वित्तीय सहायता:** त्वरित निपटान के लिए प्रत्यक्ष बैंक हस्तांतरण और ई-वॉलेट।
  - लेन-देन के इतिहास के आधार पर सूक्ष्म ऋण उपलब्ध कराने के लिए फिनटेक साझेदारियाँ।
- **सरलीकृत अंतरराज्यीय व्यापार:** विनियामक अनुपालन को आसान बनाने के लिए एकीकृत डिजिटल पास की शुरूआत।
  - उपज की मुक्त आवाजाही को सुविधाजनक बनाने के लिए मानकीकृत कर एवं अनुपालन ढाँचा।
- **मोबाइल पहुँच और स्थानीय भाषा समर्थन:** e-NAM ऐप पर आवाज आधारित कमांड और स्थानीय भाषा विकल्प।
  - किसानों को प्लेटफॉर्म पर नेविगेट करने में सहायता करने के लिए डिजिटल साक्षरता अभियान।

e-NAM उन्नयन का अपेक्षित प्रभाव

- **किसानों की भागीदारी में वृद्धि:** आसान पहुँच और बेहतर प्रोत्साहन से अधिक किसान आकर्षित होंगे।
- **उच्च मूल्य प्राप्ति:** प्रत्यक्ष बाजार पहुँच से मध्यस्थों में कमी आएगी, जिससे उचित मूल्य सुनिश्चित होगा।
- **हानि में कमी:** बेहतर भंडारण और परिवहन बुनियादी ढाँचे से फसल-उपरांत हानि में कमी आएगी।
- **लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में निवेश:** आपूर्ति शृंखला समाधानों में निवेश से आर्थिक विकास को गति मिलेगी।

Note: For other government initiatives to reform agricultural marketing in India, please follow the link:

https://www.nextias.com/ca/current-affairs/05-12-2024/agricultural-marketing-draft-national-policy-framework

Source: IE

भारत का सोने में निवेश 2024 में 60% बढ़कर 1.5 लाख करोड़ रुपये हो जाएगा

संदर्भ

- विश्व स्वर्ण परिषद (WGC) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में सोने में निवेश 2023 की तुलना में 2024 में 60% बढ़कर 18 बिलियन डॉलर (लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपये) तक पहुँच जाएगा।

रिपोर्ट के मुख्य अंश

- भारत की सोने की निवेश माँग 2024 में 239 टन रही, जो 2013 के पश्चात् का उच्चतम स्तर है।
  - यह 2023 में दर्ज 185 टन से 29% की वृद्धि दर्शाता है।
- वैश्विक सोने की माँग में भी 25% की वृद्धि देखी गई, जो 2023 में 945.5 टन होगी।
- गोल्ड एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETFs) और म्यूचुअल फंड में माँग में और वृद्धि होने की संभावना है।

सोने से संबंधित मुख्य तथ्य

- **भारत में भंडार:** बिहार (44%), उसके पश्चात् राजस्थान (25%), कर्नाटक (21%), पश्चिम बंगाल (3%), आंध्र प्रदेश (3%), और झारखंड (2%)।
- **विश्व में भंडार:** संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, इटली और फ्रांस।

वृद्धि के कारण

- **सोने की कीमतों में लगातार वृद्धि:** इस उछाल का मुख्य कारण पूरे वर्ष सोने की कीमतों में लगातार वृद्धि होना है।
  - निवेशकों ने मुद्रास्फीति और आर्थिक अस्थिरता से बचाव के लिए सोने की ओर रुख किया।
- **सांस्कृतिक माँग:** विवाह जैसे शुभ अवसरों पर सोने के प्रति पारंपरिक पसंद के कारण खुदरा माँग में वृद्धि हुई और सोने की खरीद में काफी वृद्धि हुई।
- **शहरी खरीदारी प्रवृत्तियाँ:** महानगरीय शहरों में खरीदारी गतिविधि में वृद्धि देखी गई।
  - ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्मों द्वारा छोटे सोने के निवेश बार और सिक्कों की त्वरित डिलीवरी की पेशकश से निवेश में आसानी हुई।
- **अन्य परिसंपत्ति वर्गों का कमजोर प्रदर्शन:** घरेलू शेयर बाजारों ने औसत रिटर्न दर्ज किया, जिससे निवेशकों का रुझान सोने की ओर बढ़ा।

भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव

- **चालू खाता घाटा (CAD):** अधिक सोने के आयात से भारत का चालू खाता घाटा बढ़ सकता है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार प्रभावित हो सकता है।
- **उच्च मुद्रास्फीति दबाव:** सोने की माँग में वृद्धि से इसकी कीमत बढ़ जाती है, जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति दबाव बढ़ जाता है।
- **वित्तीय बाजार में व्यवधान:** सोने की ओर निवेश का रुझान बढ़ने से इक्विटी बाजारों में तरलता कम हो सकती है, जिससे शेयर बाजार का प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है।

आगे की राह

- **स्वर्ण मुद्रीकरण योजनाएँ:** आयात पर निर्भरता कम करने के लिए बैंकों में सोना जमा करने को प्रोत्साहित करना।

- **गोल्ड ETFs और म्यूचुअल फंड को मजबूत करना:** डिजिटल गोल्ड निवेश के लिए कर प्रोत्साहन प्रदान करना।
- **ई-गोल्ड इन्फ्रास्ट्रक्चर:** फिनटेक प्लेटफार्मों के माध्यम से डिजिटल गोल्ड निवेश की पहुँच का विस्तार करना।

विश्व स्वर्ण परिषद (WGC)

- WGC स्वर्ण उद्योग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संघ है, जिसका गठन 1987 में विश्व की कुछ सबसे अग्रणी खनन कंपनियों द्वारा किया गया था।
- **शासन:** विश्व स्वर्ण परिषद का शासन निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है, जिसमें सदस्य कंपनी के प्रतिनिधि (अध्यक्ष या मुख्य कार्यकारी अधिकारी) और विश्व स्वर्ण परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शामिल होते हैं।
- **सदस्य:** विश्व स्वर्ण परिषद के 32 सदस्य।
- इसका मुख्यालय लंदन में है तथा इसके कार्यालय भारत, चीन, सिंगापुर, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका में हैं।

Source: DDNews

फेसियल रिकॉग्निशन सिस्टम (FRS)

संदर्भ

- महाराष्ट्र सरकार ने सरकारी कार्यों में सुरक्षा और दक्षता में सुधार के लिए मंत्रालय में प्रवेश के लिए फेसियल रिकॉग्निशन सिस्टम तकनीक प्रारंभ की है।

फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम क्या है?

- फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम एक ऐसी तकनीक है जो डिजिटल छवि या वीडियो फ्रेम से मानवीय चेहरे का मिलान चेहरों के डेटाबेस से करने में सक्षम है।
- FRS की मुख्य प्रौद्योगिकियाँ इस प्रकार हैं;
  - **कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI):** मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग, प्रणालियों को समय के साथ सटीकता में सुधार करने में सक्षम बनाती है।
  - **कंप्यूटर विज़न:** यह छवियों और वीडियो से दृश्य डेटा निकालता है, उसका विश्लेषण करता है और उसकी व्याख्या करता है।
  - **बायोमेट्रिक विश्लेषण:** यह प्रमाणीकरण के लिए चेहरे की विशिष्ट विशेषताओं की पहचान करता है।
  - **तंत्रिका नेटवर्क (CNNs):** यह छवि पहचान और फीचर निष्कर्षण के लिए आवश्यक है।

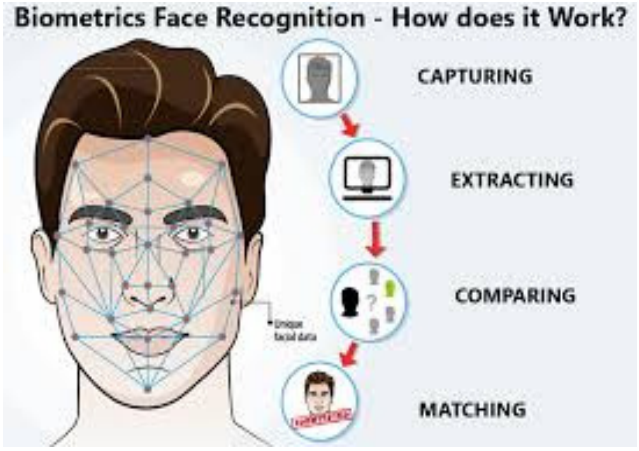

फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम के उदाहरण

- **अमेज़न रिकॉग्निशन:** एक क्लाउड-आधारित सेवा जो छवियों और वीडियो का विश्लेषण करने के लिए चेहरे की पहचान का उपयोग करती है।
- **माइक्रोसॉफ्ट एज़्योर फेस API:** एक फेशियल रिकॉग्निशन API जो माइक्रोसॉफ्ट की क्लाउड कंप्यूटिंग सेवाओं का हिस्सा है।
- **डीपफेस:** फेसबुक द्वारा विकसित एक चेहरा पहचान कार्यक्रम।

फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम के अनुप्रयोग

- **सुरक्षा एवं निगरानी:** इसका उपयोग कानून प्रवर्तन, सीमा नियंत्रण और सार्वजनिक स्थान की निगरानी में सुरक्षा बढ़ाने के लिए किया जाता है।
- **एक्सेस नियंत्रण और प्रमाणीकरण:** यह डिवाइसों को अनलॉक करता है, कार्यस्थलों को सुरक्षित करता है, और डिजिटल लॉगिन के लिए पासवर्ड को प्रतिस्थापित करता है।
- **वित्तीय सेवाएँ:** यह सुरक्षित बैंकिंग, धोखाधड़ी का पता लगाने और संपर्क रहित भुगतान को सक्षम बनाता है।
- **स्वास्थ्य देखभाल:** इसका उपयोग रोगियों की पहचान करने, निदान में सहायता करने और मानसिक स्वास्थ्य की निगरानी करने के लिए किया जाता है।
- **खुदरा एवं विपणन:** यह ग्राहक अनुभव को बढ़ाता है, लक्षित विज्ञापनों को सक्षम बनाता है, और दुकानों में चोरी को रोकता है।

FRS की चिंताएँ

- **गोपनीयता का उल्लंघन:** अनधिकृत निगरानी और डेटा संग्रहण, बिना सहमति के व्यक्तियों की गोपनीयता का उल्लंघन करता है।
- **डेटा सुरक्षा जोखिम:** चेहरे की पहचान करने वाले डेटाबेस हैकिंग के प्रति संवेदनशील होते हैं, जिससे पहचान की चोरी और डेटा का दुरुपयोग हो सकता है।
- **पूर्वाग्रह और अशुद्धि:** अध्ययनों से पता चला है कि चेहरे की पहचान करने वाली प्रणालियों में अश्वेत लोगों, महिलाओं और गैर-द्विआधारी व्यक्तियों के लिए त्रुटि दर अधिक होती है, जिसके कारण गलत गिरफ्तारियाँ एवं गलत पहचान होती है।
- **प्रोफाइलिंग के लिए दुरुपयोग:** सरकारें और निगम नस्लीय प्रोफाइलिंग और घुसपैठिया विज्ञापन के लिए प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग करते हैं।
- **डीपफेक:** AI-जनित डीपफेक पहचान में हेरफेर कर सकते हैं, जिससे बायोमेट्रिक सुरक्षा कमजोर हो सकती है।

आगे की राह

- सरकारों को व्यापक स्तर पर निगरानी और चेहरे की पहचान तकनीक के दुरुपयोग को रोकने के लिए स्पष्ट कानून स्थापित करने चाहिए।
- चेहरे की पहचान से संबंधित डेटाबेस को उल्लंघन और पहचान की चोरी से बचाने के लिए सख्त साइबर सुरक्षा उपायों को लागू किया जाना चाहिए।

Source: IE

भारत ने 100 GW सौर ऊर्जा क्षमता का ऐतिहासिक माइलस्टोन प्राप्त किया

समाचार में

- भारत ने 100 गीगावाट (GW) की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता को पार करके अपनी नवीकरणीय ऊर्जा यात्रा में एक महत्त्वपूर्ण माइलस्टोन प्राप्त कर लिया है।

विकास और उपलब्धियाँ

- पिछले दशक में भारत की सौर ऊर्जा क्षमता 35 गुना बढ़ गई है, जो 2014 में 2.82 गीगावाट से बढ़कर 2025 में 100 गीगावाट हो जाएगी।
- 31 जनवरी, 2025 तक भारत की कुल स्थापित सौर क्षमता 100.33 गीगावाट है, जिसमें से 84.10 गीगावाट कार्यान्वयन के अधीन है और 47.49 गीगावाट निविदा के अधीन है।
- रूफटॉप सौर क्षेत्र में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, 2024 में 4.59 गीगावाट की नई क्षमता स्थापित की जाएगी, जो 2023 की तुलना में 53% की वृद्धि दर्शाती है।
- राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश उपयोगिता-स्तरीय सौर स्थापनाओं में महत्त्वपूर्ण योगदान देने वाले शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल हैं।
- भारत की सौर विनिर्माण क्षमता 2014 में 2 गीगावाट से बढ़कर 2024 में 60 गीगावाट हो गई है, जिससे देश सौर मॉड्यूल उत्पादन में वैश्विक अग्रणी बन गया है, तथा 2030 तक 100 गीगावाट का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा गया है।

भारत के लिए सौर ऊर्जा का महत्त्व

- **ऊर्जा सुरक्षा:** सौर ऊर्जा जीवाश्म ईंधन और आयात पर निर्भरता को कम करने में सहायता करती है, जिससे भारत बिजली उत्पादन में अधिक आत्मनिर्भर बन जाता है।
- **पर्यावरणीय लाभ:** सौर ऊर्जा एक स्वच्छ और सतत ऊर्जा स्रोत है, जो ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करता है और जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करता है।
- **आर्थिक विकास:** सौर उद्योग ने स्थापना, रखरखाव और विनिर्माण में लाखों रोजगार उत्पन्न किए हैं, जिससे रोजगार के अवसर बढ़े हैं।
- **लागत-प्रभावशीलता:** सौर फोटोवोल्टिक (PV) पैनलों की गिरती लागत ने सौर ऊर्जा को पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का एक किफायती विकल्प बना दिया है।
- **ग्रामीण विद्युतीकरण:** सौर ऊर्जा दूरदराज और ऑफ-ग्रिड क्षेत्रों में विद्युतीकरण के लिए एक प्रभावी समाधान प्रदान करती है, जिससे लाखों भारतीयों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार होता है।

सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रमुख सरकारी पहल

- **राष्ट्रीय सौर मिशन (NSM):** 2010 में प्रारंभ किए गए इस मिशन का लक्ष्य 2030 तक 280 गीगावाट स्थापित सौर क्षमता प्राप्त करना है।

- **प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना:** यह एक परिवर्तनकारी योजना है जो छत पर सौर ऊर्जा को घरेलू वास्तविकता बना रही है तथा घरों को स्वच्छ ऊर्जा से सशक्त बना रही है।
- **PM-KUSUM योजना:** सौर सिंचाई पंपों और ग्रिड से जुड़े नवीकरणीय ऊर्जा समाधानों को बढ़ावा देकर किसानों को समर्थन देने के लिए बनाई गई है।
- **सौर पार्क योजना:** क्षमता विस्तार को बढ़ावा देने के लिए व्यापक स्तर पर सौर पार्कों के विकास की सुविधा प्रदान करती है।
- **उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (PLI) योजना:** सौर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल के घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहित करती है, जिससे आयात पर निर्भरता कम होती है।
- **नेट मीटरिंग नीति:** आवासीय और वाणिज्यिक उपभोक्ताओं को अपनी स्वयं की सौर ऊर्जा उत्पन्न करने और अधिशेष विद्युत ग्रिड को बेचने की अनुमति देती है।
- **अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन (ISA):** सौर ऊर्जा संपन्न देशों के बीच सौर ऊर्जा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए भारत के नेतृत्व में एक वैश्विक पहल।

चुनौतियाँ और आगे की राह

- **भूमि अधिग्रहण:** व्यापक स्तर पर सौर परियोजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता एक बाधा बनी हुई है।
- **ग्रिड एकीकरण:** विद्युत ग्रिड में अन्तरालित सौर ऊर्जा को एकीकृत करते हुए स्थिरता और दक्षता सुनिश्चित करना।
- **वित्तीय बाधाएँ:** दीर्घकालिक विकास को बनाए रखने के लिए बुनियादी ढाँचे और तकनीकी प्रगति में निवेश की आवश्यकता है।
- **भंडारण समाधान:** स्थिर विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए लागत प्रभावी ऊर्जा भंडारण समाधान का विकास महत्त्वपूर्ण है।

Source: PIB

संक्षिप्त समाचार

अभियुक्त को गिरफ़्तारी के आधार की जानकारी देना संवैधानिक आवश्यकता

संदर्भ

- भारत के उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि किसी अभियुक्त को गिरफ्तारी के आधार की जानकारी देना महज औपचारिकता नहीं बल्कि एक अनिवार्य संवैधानिक आवश्यकता है।

उच्चतम न्यायालय का निर्णय

- न्यायालय ने कहा कि अभियुक्त को गिरफ्तारी के कारणों की जानकारी न देना संविधान के अनुच्छेद 22, भाग III के तहत प्रदत्त मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।
  - सूचना इस प्रकार दी जानी चाहिए कि गिरफ्तारी के आधार को अभियुक्त तक उसकी समझ में आने वाली भाषा में प्रभावी ढंग से पहुँचाया जा सके।
- अदालत ने अनुच्छेद 21 का भी उदाहरण दिया और कहा कि कानूनी प्रक्रिया के अतिरिक्त किसी भी व्यक्ति को उसकी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता।

संवैधानिक प्रावधान

- **भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22(1)** में कहा गया है; गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तारी के आधारों के बारे में यथाशीघ्र सूचित किए बिना हिरासत में नहीं रखा जाएगा।
  - गिरफ्तार व्यक्ति को अपनी पसंद के कानूनी सलाहकार से परामर्श करने तथा बचाव कराने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा।

महत्त्व

- **कानून प्रवर्तन पर साक्ष्य का भार:** यदि कोई अभियुक्त अनुच्छेद 22(1) के उल्लंघन का आरोप लगाता है, तो पुलिस को आदेश के अनुपालन को साबित करना होगा।
- **न्यायिक निरीक्षण:** न्यायिक मजिस्ट्रेट को रिमांड देते समय यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि अनुच्छेद 22(1) और अन्य कानूनी सुरक्षा उपायों का अनुपालन किया गया है या नहीं।

Source: TH

राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग

समाचार में

- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग (NCSK) के कार्यकाल को 31 मार्च, 2028 तक बढ़ाने को मंजूरी दे दी है, जिससे लगभग 51 करोड़ रुपये का वित्तीय भार पड़ेगा।

राष्ट्रीय सफ़ाई कर्मचारी आयोग (NCSK) के बारे में

- इसकी स्थापना 12 अगस्त 1994 को राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग अधिनियम, 1993 के अंतर्गत एक वैधानिक निकाय के रूप में 3 वर्ष की अवधि के लिए की गई थी।
- अधिनियम को 2004 तक बढ़ा दिया गया, जिसके पश्चात् आयोग सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन एक गैर-सांविधिक निकाय बन गया।
- आयोग मीडिया रिपोर्टों या टिप्पणियों के आधार पर सफाई कर्मचारियों को प्रभावित करने वाले मुद्दों पर स्वतः संज्ञान लेता है।
- **संरचना:** आयोग में एक अध्यक्ष (केन्द्रीय राज्य मंत्री स्तर), एक उपाध्यक्ष (सचिव स्तर), पाँच सदस्य (एक महिला सदस्य सहित) और एक सचिव (संयुक्त सचिव स्तर) होते हैं।
- **आयोग का अधिदेश:** सफाई कर्मचारियों के लिए असमानताओं को समाप्त करने हेतु कार्यक्रमों की सिफारिश करना।
  - सफाई कर्मचारियों और मैला ढोने वालों के लिए सामाजिक और आर्थिक पुनर्वास कार्यक्रमों का मूल्यांकन और अध्ययन करना।
  - सरकारी निकायों सहित विभिन्न नियोक्ताओं द्वारा नियोजित सफाई कर्मचारियों की कार्य स्थितियों (स्वास्थ्य, सुरक्षा, मजदूरी) की निगरानी करना।
  - विस्तारित अधिदेश (2013 के पश्चात्): "मैनुअल स्कैवेंजर के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013" के अधिनियमन के पश्चात्, आयोग का कार्यक्षेत्र अधिनियम के कार्यान्वयन की निगरानी तक विस्तारित हो गया।
    - अधिनियम के कार्यान्वयन न होने पर स्वतः संज्ञान लें।
  - **उच्चतम न्यायालय का निर्णय (2023):** आयोग मैनुअल स्कैवेंजिंग को समाप्त करने के लिए उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के कार्यान्वयन की निगरानी करता है।
    - निर्देश में मैनुअल स्कैवेंजिंग से संबंधित मुआवजा, पुनर्वास उपाय और जवाबदेही तंत्र की स्थापना सम्मिलित है।

Source: IE

शतावरी (एस्पेरेगस रेसमोसस)

संदर्भ

- आयुष मंत्रालय ने शतावरी के औषधीय और स्वास्थ्य लाभों को बढ़ावा देने के लिए "शतावरी - बेहतर स्वास्थ्य के लिए" नामक एक अभियान प्रारंभ किया है।

परिचय

- शतावरी (एस्पेरेगस रेसमोसस) एक औषधीय पौधा है जिसका उपयोग भारतीय चिकित्सा की पारंपरिक प्रणाली आयुर्वेद में व्यापक रूप से किया जाता है।
- **विशेषताएँ:** शतावरी एक चढ़ने वाला पौधा है जिसके तने 4 मीटर तक लंबे हो सकते हैं।
  - इसमें रेशेदार और कंदीय दोनों प्रकार की जड़ों वाली एक अपस्थानिक जड़ प्रणाली होती है, जो लगभग एक मीटर लंबी होती है और दोनों सिरों पर पतली होती जाती है।
- **वितरण:** यह अफ्रीका से दक्षिणी एशिया, भारतीय उपमहाद्वीप सहित, उत्तरी ऑस्ट्रेलिया तक फैला हुआ है।
- **उपयोग:** यह पौधा अपने एडाप्टोजेनिक (शरीर की प्रणालियों को विनियमित करने और तनाव के प्रति प्रतिरोध में सुधार करने में सहायता करता है) और कायाकल्प गुणों के लिए जाना जाता है, विशेष रूप से महिलाओं के स्वास्थ्य और समग्र प्रतिरक्षा में।

Source: PIBUSAID

संयुक्त राज्य अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (USAID)

संदर्भ

- डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन सरकार पुनर्गठन प्रयास के तहत अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी (USAID) के कर्मचारियों की संख्या में कटौती करने जा रहा है।

USAID के संबंध में

- **इतिहास:** इसकी स्थापना 1961 में अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी द्वारा सोवियत संघ के साथ संयुक्त राज्य अमेरिका के शीत युद्ध संघर्ष के चरम पर की गई थी।
- **महत्त्व:** USAID अमेरिकी विदेश नीति का एक महत्त्वपूर्ण अंग है, जिसका उपयोग गठबंधनों को मजबूत करने, कूटनीतिक प्रभाव डालने, तथा आपदाओं से उबरने वाले देशों की सहायता करने, गरीबी से लड़ने और लोकतांत्रिक सुधारों को बढ़ावा देने के माध्यम से वैश्विक विकास का समर्थन करने के लिए किया जाता है।
- **सहायता प्राप्तकर्ता (2023):** एजेंसी ने 130 से अधिक देशों को सहायता प्रदान की, जिनमें यूक्रेन, इथियोपिया, जॉर्डन, सोमालिया और अफगानिस्तान शीर्ष लाभार्थी हैं।
- **कार्यबल:** इसमें विश्व भर में 10,000 से अधिक लोग कार्यरत हैं, जिनमें से दो-तिहाई अमेरिका के बाहर कार्य करते हैं। हालाँकि, ट्रम्प के पुनर्गठन का लक्ष्य कर्मचारियों की संख्या को 10,000 से घटाकर केवल 300 करना है।

क्या आप जानते हैं?

- USAID ने 1965 में भारत को मद्रास (अब चेन्नई) में एक रासायनिक उर्वरक कारखाना बनाने के लिए 67 मिलियन डॉलर का ऋण दिया था, इस शर्त पर कि वितरण का प्रभार भारत सरकार के बजाय एक निजी अमेरिकी कंपनी के पास होगा, तथा इस क्षेत्र में कोई अतिरिक्त उर्वरक संयंत्र नहीं बनाया जाएगा।

Source: IE

एल्गो ट्रेडिंग फ्रेमवर्क

समाचार में

- भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने हाल ही में एल्गोरिथम (एल्गो) ट्रेडिंग में खुदरा निवेशकों की सुरक्षित भागीदारी को सुविधाजनक बनाने के लिए एक ढाँचा पेश किया है।

आवश्यकता क्यों?

- इस कदम का उद्देश्य पारंपरिक रूप से संस्थागत निवेशकों के प्रभुत्व वाली उन्नत ट्रेडिंग रणनीतियों तक पहुँच को लोकतांत्रिक बनाना है।

एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग के बारे में

- एल्गोरिदमिक ट्रेडिंग में पूर्वनिर्धारित रणनीतियों के आधार पर ट्रेडों को निष्पादित करने के लिए कंप्यूटर एल्गोरिदम का उपयोग शामिल है, जिससे बड़ी मात्रा में डेटा का तेजी से प्रसंस्करण और तीव्रता से ऑर्डर निष्पादन संभव हो पाता है।

खुदरा भागीदारी के लिए SEBI का ढाँचा

- SEBI का नया ढाँचा खुदरा निवेशकों को पंजीकृत ब्रोकरों के माध्यम से एल्गो ट्रेडिंग में शामिल होने की अनुमति देता है।
- ब्रोकरों को खुदरा ग्राहकों को दी जाने वाली प्रत्येक एल्गोरिथम रणनीति के लिए स्टॉक एक्सचेंजों से अनुमोदन प्राप्त करना होगा।
- पारदर्शिता सुनिश्चित करने और ऑडिट ट्रेल बनाए रखने के लिए सभी एल्गो ऑर्डरों को स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा प्रदान किए गए एक अद्वितीय पहचानकर्ता के साथ टैग किया जाएगा।
- ब्रोकरों को दो-कारक प्रमाणीकरण और स्थिर आईपी जैसे उपायों के साथ सुरक्षित एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (APIs) को लागू करना आवश्यक है।

व्हाइट-बॉक्स बनाम. ब्लैक-बॉक्स एल्गोरिदम

- **व्हाइट-बॉक्स एल्गोज़:** ये पारदर्शी और प्रतिकृति योग्य एल्गोरिदम हैं। खुदरा निवेशक इनका स्वतंत्र रूप से उपयोग कर सकते हैं, बशर्ते वे आवश्यक आवश्यकताओं को पूरा करते हों तथा ब्रोकरों एवं एक्सचेंजों के साथ पंजीकृत हों।
- **ब्लैक-बॉक्स एल्गोज़:** स्वामित्व वाली प्रणालियाँ जहाँ अंतर्निहित तर्क का प्रकटीकरण नहीं किया जाता। ऐसे एल्गो प्रदाताओं को एक्सचेंजों के साथ अनुसंधान विश्लेषक के रूप में पंजीकरण कराना होगा तथा उनके द्वारा प्रस्तुत प्रत्येक एल्गो के लिए विस्तृत अनुसंधान रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।

Source: LM

पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन(NBM)

संदर्भ

- पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन (NBM) ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और आयात निर्भरता को कम करने में सहायता की है।

पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन (NBM)

- बांस की खेती, मूल्य संवर्धन और बाजार एकीकरण को बढ़ावा देने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना (CSS) के रूप में 2018-19 में पुनर्गठित राष्ट्रीय बांस मिशन (NBM) प्रारंभ किया गया था।
- **उद्देश्य:** यह गैर-वनीय भूमि में बांस के प्रसार एवं खेती, बांस उपचार, बाजारों की स्थापना, इन्क्यूबेशन केंद्रों, मूल्यवर्धित उत्पाद विकास और प्रसंस्करण तथा उपकरणों व उपकरणों के विकास के लिए सहायता प्रदान करता है।
- केन्द्र और राज्यों के बीच वित्तपोषण का अनुपात 60:40 है (पूर्वोत्तर और पहाड़ी राज्यों के लिए 90:10 तथा संघ शासित प्रदेशों के लिए 100% को छोड़कर)।

NBM का विकास

- राष्ट्रीय बांस मिशन (NBM) को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत 2006 में प्रारंभ किया गया था।
  - बाद में इसे बागवानी विकास मिशन (2014-16) के अंतर्गत शामिल कर लिया गया।
- वर्ष 2018 में इसे राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन (NMSA) के अंतर्गत पुनर्गठित किया गया, जिसमें बाजार संपर्क, मूल्य संवर्धन और अनुसंधान एवं विकास पर अधिक ध्यान दिया गया।
- 2018 में भारतीय वन अधिनियम, 1927 में संशोधन करके वनों के बाहर उगाए जाने वाले बांस को वृक्षों की परिभाषा से हटा दिया गया, जिससे इसकी खेती और व्यापार आसान हो गया।

Source: PIB

भारत की सबसे बड़ी सौर सेल बनाने वाली इकाई

संदर्भ

- तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने गंगईकोंडान SIPCOT औद्योगिक विकास केंद्र में भारत की सबसे बड़ी सौर सेल और मॉड्यूल विनिर्माण इकाई का उद्घाटन किया।

परिचय

- गंगईकोंडान SIPCOT औद्योगिक विकास केन्द्र तमिलनाडु के तिरुनेलवेली के गंगईकोंडान गाँव में एक औद्योगिक पार्क है।
  - इसकी स्थापना टाटा पावर की सौर ऊर्जा विनिर्माण शाखा, TP सोलर लिमिटेड द्वारा की गई थी।
- **क्षमता:** यह सुविधा सौर ऊर्जा उत्पादन इकाइयों के लिए फोटोवोल्टिक सेल और मॉड्यूल का उत्पादन करेगी, जिसकी वार्षिक क्षमता लगभग 4 गीगावाट होगी।
- **उत्पादन:** यह इकाई 182 मिमी के मोनो और 158.25 मिमी आकार के मल्टी-क्रिस्टलाइन सेल का उत्पादन करेगी।

Source: TH

ट्रोपेक्स (TROPEX) अभ्यास

समाचार में

- भारतीय नौसेना का थिएटर स्तरीय ऑपरेशनल अभ्यास (TROPEX) का 2025 संस्करण वर्तमान में हिंद महासागर क्षेत्र में चल रहा है।

अभ्यास के बारे में

- यह अभ्यास द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया जाता है और तीन महीने (जनवरी-मार्च 2025) तक चलता है।
- **प्रतिभागी:** सभी परिचालनशील भारतीय नौसेना इकाइयाँ, साथ ही भारतीय सेना, वायु सेना और तटरक्षक संपत्तियाँ।
  - इसमें लगभग 65 भारतीय नौसेना जहाज, 9 पनडुब्बियाँ और विभिन्न प्रकार के 80 से अधिक विमान भाग ले रहे हैं।
- **उद्देश्य:** विगत कुछ वर्षों में इस अभ्यास का दायरा और जटिलता बढ़ती गई है।
  - यह समन्वित योजना, सटीक लक्ष्य निर्धारण, युद्ध प्रभावशीलता और विश्वसनीय संयुक्त संचालन पर केंद्रित है।
  - इसका उद्देश्य भारतीय नौसेना के मूल युद्ध कौशल को प्रमाणित करना है।
  - इसका उद्देश्य पारंपरिक, असममित और संकर खतरों के विरुद्ध राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा के लिए समन्वित, एकीकृत प्रतिक्रिया सुनिश्चित करना भी है।

Source: TH

■■■■